सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 193, पृष्ठः 8+4

अब पेट्रोल-डीजल के दाम होंगे कम!

» Pg 12

इनसाइड आधार के लिए बच्चे नहीं अफसर दौड़ें : एसडीएम... » Pg 04

प्रेमी के प्यार में पागल रोशनी ने मां-बेटी के रिश्ते को किया कलंकित

छाती पर खड़ी होकर बेटी को मारा

लाश बेड में रख प्रेमी संग सोई, आखिर कितना गिर सकती है एक मां?

सायनारा, बेटी

रोशनी खान, हत्यारोपी मां

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। देश में प्यार में पागलपन के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। नहीं, नहीं इस बार किसी प्रेमी की हत्या नहीं की गई है, इस बार तो प्यार में पागल मां ने प्रेमी संग मिलकर अपनी बेटी की छाती में चढ़कर उसकी हत्या की और फिर कीड़े पड़ते शव के सामने डांस कर प्रेमी संग दारू पार्टी कर रही थी। मामला लखनऊ का है। कैसरबाग के खंदारी बाजार में रहने वाले शाहरुख की रोशनी उर्फ नाज से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के 7 साल की बेटी सायनारा उर्फ सोना थी। रोशनी बार डांसर है। 4 साल से एक युवक से उसका संबंध है। उसके साथ रहने के लिए जेठ, सास और 2 ननदों को रेप के केस में फंसा जेल भिजवा चुकी है। पति को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। उसके बाद प्रेमी के साथ अपनी ससुराल में ही लिव-इन में रहने लगी थी।

रोशनी खान और प्रेमी उदित।

क्या हुआ था उस दिन?

उदित ने बताया कि, रोशनी का पति और परिजन रिश्ते का विरोध कर रहे थे। प्लानिंग के तहत पहले रोशनी के जेठ, सास और दोनों ननदों को जेल भिजवा दिया था। 13 जुलाई को रोशनी ने बॉयफ्रेंड उदित ने मिलकर 7 साल की बेटी सायनारा का गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। जब उसकी मौत हो गई तो रोशनी उसके पेट पर पैर रखकर चढ़ गई। इससे उसके मुंह से खून निकल आया। फिर शव को बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। रोशनी ने बताया कि जब बदबू आने लगी तो उसने और उदित ने शव को बाहर निकाला और एसी के सामने रख दिया। फिर शव पर परफ्यूम छिड़ककर बदबू कम करने की कोशिश की और फिर शव के सामने ही शराब पार्टी की और ड्रग्स भी लिए।

हत्या की पुष्टि हुई

सोना के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि सोना की मौत दम घुटने से हुई है। यानी उसका मुंह दबाकर गला घोंटा गया। पोस्टमार्टम से 36 से 48 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी।

रोशनी ने किया कॉल : 14-15 जुलाई की रात करीब 3 बजे रोशनी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि पति ने बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस पहुंची तो रोशनी ने बताया कि पति शाहरुख घर आया था। झगड़े के दौरान बेटी की हत्या करके भाग गया। पुलिस ने शव देखा तो मामला कुछ और ही लगा। शव से बदबू आ रही थी और कीड़े भी पड़ गए थे। इससे साफथा कि हत्या एक-दो दिन पहले की गई थी। पुलिस का शक रोशनी और उदित पर गहराया। पूछताछ की उदित ने सच बयां कर दिया। उसने बताया कि उसकी रोशनी से 4 साल पहले क्लब में मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों करीब आए और लिव-इन में रहने लगे। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 13 जुलाई की दोपहर रोशनी ने बेटी की हत्या की। शव को कमरे में बंद कर प्रेमी के साथ होटल में चली गई। रातभर होटल में रही। 14 जुलाई को घर लौटी। शव से बदबू आने पर रात में पुलिस को फोन किया। रोशनी और उदित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घोषणा

इस गुट ने ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी

अमेरिका ने पाकिस्तानी गुट टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका ने शुक्रवार को पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीआरएफने 22 अप्रैल के पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' (एफटीओ) और एक विशेष रूप से नामित 'वैश्विक आतंकवादी' (एसडीजीटी) घोषित किया।

टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी शाखा : द रेजिस्टेंस फ्रंट को कश्मीर रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है जो लश्कर-ए-तैयबा की शाखा माने जाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह पर भारत और पश्चिमी देशों में हमलों की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें नवंबर 2008 में मुंबई पर तीन दिवसीय घातक हमला भी शामिल है। जिसमें कसाब को पकड़ा गया था। रुबियो ने एक बयान में कहा कि वाशिंगटन द्वारा टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को बल मिला। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 की मौत हुई थी। टीआरएफको लश्कर-ए-तैयबा का एक अंग माना जाता है। इस आतंकी हमले के बाद परमाणु-सशस्त्र एशियाई पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को तीन दिन में ही घुटनों पर ला दिया था।

8 साल की बच्ची का बलात्कारी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया

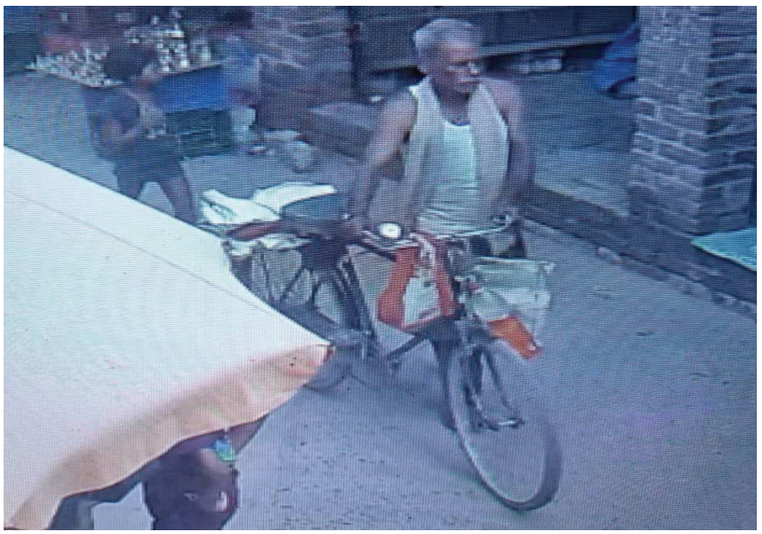

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद । जिले में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या की घटना में सीसीटीवी फुटेज में साइकिल से एक बच्ची के साथ जा रहे एक व्यक्ति ने इस बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इसके पूर्व यह व्यक्ति इस तरह की घटना कर चुका था। पुलिस ने इस अपराधी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 50000 का ईनाम घोषित किया इस अपराधी की मौजूदगी की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तारी का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस मुठभेड़ में यह व्यक्ति मारा गया। मारे गए व्यक्ति की पहचान मनु पुत्र लुटरी निवासी पखना थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद फ़र्रूख़ाबाद उम्र पैंसठ साल के रूप में हुई है बच्चियों के साथ अपराध करने वालों यही हश्र होना था क्योंकि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं।

बाबू पुरवा में 24 घंटे से बिजली गुल, सबस्टेशन पर विधायक हसन रूमी का धरना, मौके पर पुलिस बल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बाबू पुरवा सबस्टेशन पर 24 घंटे से बिजली गुल होने पर कैंट विधायक हसन रूमी क्षेत्रीय लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। उन्होंने निजीकरण को व्यवस्था की खामी बताया है।कानपुर के बाबू पुरवा सबस्टेशन पर बिजली की 24 घंटे से अधिक समय की अघोषित कटौती से परेशान होकर कैंट विधायक हसन रूमी धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रीय लोग, पार्षद पति अखिल शानू और पार्षद पति आलोक यादव भी सब-स्टेशन के अंदर मौजूद हैं।

विधायक हसन रूमी ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के निजीकरण के कारण अधिकारी और कर्मचारियों के बीच तालमेल की कमी है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के संसाधन छीने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ता बिजली कटौती के रूप में भुगत रहा है।रूमी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर साल बारिश का मौसम आता है और पेड़ों की छंटाई भी होती है, लेकिन बिजली व्यवस्था का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि केस्को के एसडीओ से बात करने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला, जिसके बाद मजबूरन उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ा है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन सबस्टेशन से कर्मचारी और अधिकारी नदारद बताए जा रहे हैं।

सार्वजनिक सूचना

! सावधान !

जी0एस0कॉलेज ऑफ लॉ खजुरहट (गंडई) बीकापुर में ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति का विवाद चल रहा है। जिसके सम्बन्ध में राजेन्द्र यादव (राजन) अनुज गोयल, संजीव कुमार गुप्ता, राजकुमार यादव, सूर्यभान आदि के विरूद्ध धोखाधड़ी का मु0थाना को0 बीकापुर में एफआईआर 318/24 पंजीकृत है। विवेचना प्रचलित है। इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में सिविलवाद Writ C3120/24 विचाराधीन है। इसी मामले में मा0 जनपद एवं सत्र न्यायालय कड़कड़डूमा कोर्ड दिल्ली में सिविलवाद ष्ट्र-624 /24 विचाराधीन है। विवाद की वजह से कालेज का संचालन नियमानुसार नहीं हो रहा है। प्राचार्य व शिक्षक सिर्फ कागजों में रह गए हैं। ब्रष्द्ध के मानक का पालन भी नही हो रहा है। इसलिए एडमिशन हेतु सावधान रहें।

एडवोकेट ए. के. तिवारी
सचिव/प्रबन्धक - जी0एस0 कॉलेज ऑफ लॉ,
खजुरहट (गंडई) बीकापुर, अयोध्या
मो0:- 9968161898

संपत्ति अनुभाग से लिपिक अमन सहित अनिरूद्ध सिंह की छुटटी

» नगर निगम के संपत्ति अनुभाग में प्रभारी अधिकारी अनिरूद्ध सिंह की अनदेखी के चलते नगर आयुक्त ने लिया एक्शन

» बारातशालाओं एवं लॉन के आवंटन में धांधली की आ रही थी शिकायतें

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम के संपत्ति अनुभाग से प्रभारी अधिकारी अनिरूद्ध सिंह एवं लिपिक अमन निगम को हटा दिया गया है। नगर आयुक्त के पास लगातार पहुंच रही मनमानी की शिकायतों पर त्वरित एक्शन लिया गया। लिपिक अमन की मिलीभगत से मोतीझील लॉन आवंटन में नगर निगम खजाने को चूना लगाने के आरोप हैं। इसपर भी कार्रवाई के संकेत हैं।

कानपुर नगर निगम की वेशकीमती अरबों रूपयों की जमीनें और संपत्तियां शहर में फैली हुई हैं। इनका अनुरक्षण एवं देखरेख संपत्ति अनुभाग करता है लेकिन बीते एक साल से प्रभारी अधिकारी अनिरूद्ध सिंह की अनदेखी के चलते संपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अनिरूद्ध सिंह के पास जोन-2 का चार्ज के साथ मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का भी प्रभार था, ऐसे में वह संपत्ति अनुभाग को समय नहीं दे पा रहे थे। इसका फायदा यहां पर तैनात लिपिक अमन निगम उठा रहा था। मोतीझील के लॉन हर साल करोडों रूपए में किराए पर उठते लेकिन धांधलियों एवं मिलीभगत के चलते गत वित्तीय वर्ष में लॉन के लिए संस्थाएं नहीं आई। मई 2025 में लॉन नंबर 2 अगले वित्तीय वर्ष के लिए महज 26 लाख रूपए में बुक कर लिया गया, जब कि इसके लिए मेयर या नगर आयुक्त से अनुमति तक नहीं ली गई। सूत्रों का दावा था कि लॉन नंबर 2 जानबूझकर बुक किया गया क्यों कि इसके बाद दूसरी कोई संस्था लॉन 1 और 2 बुक नहीं करवा सकती क्यों यह लॉन बीच में आता है। ऐसे में इसका सीधा नुकसान नगर निगम खजाने को हुआ। इसके अलावा कई अन्य प्रकरण भी नगर आयुक्त सुधीर कुमार के पास पहुंचे थे, जिनपर उन्होने नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने बताया कि लिपिक अमन निगम को शिकायतों के क्रम में लेखा विभाग में भेज दिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि वह संपत्ति में दखल न दे, जल्द ही प्रभारी की तैनाती कर दी जाएगी।

भाजपा पार्षद मोनू गुप्ता पर तीसरी एफआईआर

चौक सर्राफा के आभूषण कारोबारी ने लगाया रंगदारी मांगने का आरोप

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। भाजपा से पार्षद अभिषेक उर्फ मोनू गुप्ता के लिए मुश्किलें बढती जा रही हैं। उनपर गुरूवार को तीसरी एफआईआर रंगदारी मांगने एवं धमकाने को लेकर दर्ज की गई है। दो हफते में तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है।

कोतवाली क्षेत्र के गिलिश बाजार निवासी सर्राफा कारोबारी कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि वह चौक सर्राफा में आभूषण कारोबारी हैं। क्षेत्रीय पार्षद मोनू गुप्ता ने उनसे 10 लाख रूपए की रंगदारी मांगी है न देने पर केडीए से उनका मकान ध्वस्त कराने का आरोप लगाया गया है। वहीं, कुलदीप का आरोप हैं कि पार्षद मोनू क्षेत्र में उगाही करते हैं और खुलेआम कहते हैं कि उनका भाई कचहरी में अधिवक्ता है तुम्हे क्षेत्र में भी मारेंगे और कचहरी में भी।

भाजपा पार्षद मोनू गुप्ता

इसके पूर्व मोनू गुप्ता पर पहला मुकदमा शमीम अख्तर नाम की महिला ने दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा मोनू की चाची नीरा गुप्ता ने लिखवाया था। इन आरोपों को लेकर पार्षद मोनू गुप्ता का कहना है कि यह सभी लोग मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए साजिश रच रहे हैं। इसमें मेरे विरोधी लगे हुए हैं। पुलिस को अपना रखा है, किसी के पास कोई सुबूत नहीं है।

आधार के लिए बच्चे नहीं अफसर दौड़ें : एसडीएम

टास्क फोर्स की बैठक में योजनाओं से वंचित बच्चों पर जताई चिंता, अफसरों को दी सख्ती से काम करने की हिदायत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को उपजिलाधिकारी संजीव दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय एसडीएम टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए।

खंड शिक्षा अधिकारी रवी कुमार सिंह ने बैठक में बताया कि कई छात्र-छात्राएं जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण विद्यालयों में प्रवेश और विभिन्न शासकीय योजनाओं से वंचित हैं। इस पर एसडीएम ने नाराज़गी जताते हुए निर्देश दिया कि बच्चों को दस्तावेज़ों के लिए तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि यह कार्य ग्राम स्तर पर ही सुनिश्चित हो। उन्होंने खंड विकास अधिकारी और पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी कि वे हर बच्चे के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र गांव में ही तैयार करवाएं। मिड डे मील योजना की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भोजन हमेशा निर्धारित मीनू के अनुसार ही तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि हर सोमवार को फल और बुधवार को दूध का वितरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। यदि खाद्यान्न की कमी से भोजन व्यवस्था प्रभावित होती है तो इसके लिए पूर्ति विभाग जिम्मेदार माना जाएगा।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते एसडीएम संजीव कुमार दीक्षित।

विद्यालय कायाकल्प योजना पर जताया असंतोष

विद्यालय कायाकल्प योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए उपजिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष कार्य तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि बच्चों का भविष्य कागजों में नहीं, स्कूल की दीवारों और जमीन पर दिखना चाहिए।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी रवि सिंह, कमलेश कुमार, कृपाशंकर (शिवराजपुर), आनंद कुंवर पटेल (चौबेपुर), तहसीलदार अनुभव चंद्रा, नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत व रंजीत सिंह, सीएचसी से डॉ. अभिषेक, पूर्ति निरीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम की सख्ती और दिशा-निर्देशों से स्पष्ट है कि अब कागजी कार्रवाई नहीं, जमीनी बदलाव की दरकार है।

आंगनबाड़ी केंद्रों और साफ-सफाई पर फोकस

गांवों में सफाई व्यवस्था और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए एसडीएम ने एडीओ पंचायत को निर्देश दिए कि वह फील्ड में निरंतर जाकर सक्रिय रूप से कार्य करें और आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने हेतु उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

सालों से लंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की उम्मीद जागी

» प्रमाणपत्र न होने से बच्चों का नहीं हुआ स्कूलों में एडमीशन

» अभिभावक लगा रहे तहसील और अधिकारियों के चक्कर

बिल्हौर। करीब साल भर से जन्म प्रमाण पत्र और आधार न बन पाने के कारण बच्चों के अभिभावक तहसील और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उन्हें टरकाया जा रहा था। जिससे अकेले बिल्हौर तहसील में सैकड़ों बच्चे सरकारी स्कूल में प्रवेश से वंचित रह गए।

जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो दस्तावेज विभाग द्वारा मांगे जा रहे हैं अधिकांश के पास वह हैं ही नहीं। अब नए एसडीएम के आश्वासन के बाद कुछ उम्मीद जागी है। देखना है कि साल भर से जन्म प्रमाण पत्र से वंचित बच्चों का दर्द कुछ दूर हो पाता है या कि केवल कागजी खानापूर्ति तक सिमट कर रह जाता है।

गर्व

शिवाजी इंटर कॉलेज की बालक-बालिकाओं की टीमों ने जीता गोल्ड

कबड्डी में बिल्हौर की दमदार जीत, सीएम करेंगे सम्मानित

» स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर(कानपुर)। ग्रीनपार्क स्टेडियम में हुए युवा ओलंपिक कानपुर 2025 के कबड्डी मुकाबलों में बिल्हौर के शिवाजी इंटर कॉलेज चौबिगही की बालक व बालिका टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया।

प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों ने भाग लिया, लेकिन शिवाजी कालेज की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में बाजी मार ली। दिलचस्प बात यह रही कि अधिकतर खिलाड़ी गोहालियापुर के कम्पोजिट विद्यालय के पूर्व छात्र रहे। कोच इंशु की निःशुल्क मेहनत रंग लाई और खिलाड़ियों ने हर मैच में शानदार प्रदर्शन दिखाया।

कॉलेज के प्रधानाचार्य हरिकिशन कटियार ने टीम को बधाई दी। 21 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विजेता टीमों का सम्मान करेंगे।

कॉलेज की टीम की इस जीत पर राज्य अध्यापक पुरस्कार विजेता आशा कटियार, उषा पाल, मुक्ति त्रिवेदी, पुनीत बाजपेई, दिनेश द्विवेदी सहित कई लोग मौजूद रहे।

युवा ओलंपिक में जीत दर्ज करना गर्व की बात : नूर इदरीसी

बिल्हौर। विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य और सह प्रबंधक नूर इदरीसी ने कहा कि युवा ओलिम्पिक में कबड्डी में बालक एवम बालिकाओं का जीत का परचम लहराना बहुत ही अधिक गर्व की बात है। इन विद्यार्थियों ने अपने साहस, कौशल एवम खेल के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से विद्यालय का नाम रोशन किया है।

इनकी इस प्रतिभा को निखारने और इन्हें निरंतर प्रेरित करने में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की निश्चित ही महती भूमिका रही है। इनको और इनके प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशिक्षक मंडल को शुभकामनायें दीं।

सम्पादकीय

जिंदगी बचाने को पहल करे एनएचएआई

निस्संदेह, हाल के वर्षों में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे आदि का आशातीत विस्तार हुआ है। सड़कों के नेटवर्क सुधार से उपभोक्ताओं के समय व धन की बचत हुई है तो उद्योग-व्यापार को भी गति मिली है। लेकिन इससे जुड़ी तमाम विसंगतियां भी सामने आई हैं। सड़कों के त्रुटिपूर्ण डिजाइन व निर्माण में चूक को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पिछले हफ्ते मध्यप्रदेश में लगातार 40 घंटे लगे जाम से जहां हजारों लोगों को घंटों परेशान होना पड़ा, वहीं जाम में फंसकर तीन लोगों की मौत हुई है। निश्चय ही यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर शासन-प्रशासन के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई को गंभीरता से लेना चाहिए। उन तमाम आशंकाओं को टालना चाहिए जो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति के कारक बन सकते हैं। बहरहाल, मध्यप्रदेश की घटना को लेकर एनएचएआई की आलोचना की जा रही है। इस घटना के बारे में एनएचएआई के एक अधिकारी की संवेदनहीन टिप्पणी को लेकर भी सवाल उठे हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एनएचएआई के रुख को कठोर और संवेदनहीन बताया है, जो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने वाला है। दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने एनएचएआई को दोषपूर्ण और देर से सड़क निर्माण के लिये फटकार लगायी है, जिसके कारण आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के इंदौर-देवास खंड में जाम लग गया था। बताते हैं कि एनएचएआई के कानूनी सलाहकार ने इस बाबत संवेदनहीन टिप्पणी की कि लोग बिना किसी काम के घर से इतनी जल्दी क्यों निकलते हैं? इस टिप्पणी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। निश्चित रूप से इस दुर्घटना और हजारों लोगों के घंटों जाम में फंसे रहने के मामले में जहां एनएचएआई की तरफ से माफी मांगने की जरूरत थी, वहीं उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिये दोष लोगों पर लगाते हुए असंवेदनशील बयान दे डाला। जिसके खिलाफ तल्ख प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यही प्रतिक्रिया अदालत की टिप्पणी में भी झलकती है। इसमें दो राय नहीं कि अकसर बड़ी सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान अंतहीन असुविधा भारतीय यात्रियों के लिए रोजमर्रा के अनुभव हैं। अधिकांश साइटों पर निर्माण से जुड़ी, यात्रियों के अनुकूल सर्वोत्तम परंपराओं को अपनाना और यातायात में व्यवधान को कम से कम करना सुनिश्चित नहीं किया जाता है। निस्संदेह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सक्रियता व प्रतिबद्धता की अकसर सराहना होती रहती है। वे सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों को बढ़ाने को लेकर लगातार अभियान चलाते भी रहते हैं। हालांकि, वे भी मानते रहे हैं कि अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। निस्संदेह, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निरंतर यातायात को सुगम मानकों के अनुरूप बनाने के लिये प्रयासरत रहता भी है।

निश्चित रूप से स्थलों की स्थिति और भूमि अधिग्रहण के तमाम विवाद भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम राजमार्गों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जाना होना चाहिए। दरअसल, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर निर्माण फर्मों और ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। जिसमें व्यापक अनुभव, क्षमता और नैतिकता जैसे कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। निस्संदेह, काम की गुणवत्ता समस्याओं के समाधान में मददगार साबित हो सकती है।

एक साल बाद आपराधिक कानूनों की दिशा-दशा

केपी सिंह

अब समय आ गया है कि नए आपराधिक कानूनों की पहली समीक्षा की जाए ताकि मसौदा तैयार करने में हुई गलतियों को सुधारा जा सके, खामियों को दूर किया जा सके, कमियों की भरपाई की जा सके और लोगों की वास्तविक चिंताओं को खुले मन से स्वीकार करके कानूनों में आवश्यक फेरबदल किया जाए, जिससे इन कानूनों की उपयोगिता और बढ़ सके। तीन नये आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को इस उम्मीद के साथ लागू किए गए थे कि भारत में ब्रिटिश काल से चली आ रही आपराधिक न्याय प्रणाली नागरिकों को न्याय प्रदान करने और सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देने वाली एक जन-केन्द्रित, प्रगतिशील, उद्देश्यपूर्ण एवं सक्षम संस्था के रूप में बदल जाएगी। यद्यपि किसी कानून के लागू होने के बाद एक वर्ष का समय लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इसकी सफलता या विफलता के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथापि यह समय कानून के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और अवरोधों की पहचान करने के लिए पर्याप्त संकेत छोड़ जाता है।

नए कानूनों के लागू होने से पहले, कई कानून विशेषज्ञों ने उनकी उपयोगिता और व्यावहारिकता के बारे में आशंका व्यक्त की थी। यह सराहनीय है कि न्याय प्रणाली की सभी शाखाओं ने धारा-संख्या और उसमें निहित प्रावधानों में किए गए बदलावों को अच्छी तरह से स्वीकार और अंगीकार किया है। पहले दिन से ही उन्हें बिना किसी समस्या के व्यवहार में लाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में नए कानूनों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की जा रही है और उनकी जांच की जा रही है। ऐसा केवल व्यापक पैमाने पर चलाए गए प्रशिक्षण अभियान के कारण ही सम्भव हो पाया है, जिसकी परिकल्पना और योजना गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, और जिसे सभी हितधारकों द्वारा उत्साहपूर्वक अपनाया गया है। यहां तक कि विधि-विद्यालयों ने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हुए इन बदलावों को बिना किसी कठिनाई के आत्मसात कर लिया है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को नए कानूनों में सबसे अधिक वरीयता देकर यह संदेश दिया गया है कि सरकार महिलाओं और अवयस्कों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। पुलिस ने इन प्रावधानों का बखूबी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त, सज़ा के प्रावधानों का अपराध की संगीनता के अनुसार सरलीकरण करके दण्ड-विधान को सुधारात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यद्यपि इसके परिणाम कुछ वर्षों बाद ही देखने को मिल सकेंगे।

भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता सबसे महत्वपूर्ण है, और यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 48 के प्रावधानों में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस धारा में, देश के बाहर बैठकर भारत में अपराध को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 356 के अनुसार आरोपियों की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। हालांकि यह एक कटु सत्य है कि इन धाराओं का आतंकवादियों और गैंगस्टरों के खिलाफ नगण्य प्रयोग किया गया है, फलस्वरूप विदेशों में बैठकर भारत में फिरौती के लिए कॉल करने और आतंकवाद को भड़काने जैसी गतिविधियां रुक नहीं पाई हैं। मुकदमों के अनुसंधान को पारदर्शी और उच्चस्तरीय बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के प्रावधान नए कानूनों की विशेषता है। फारेंसिक जांच का दायरा अनुसंधान प्रक्रिया में बढ़ाकर जांच को निष्पक्ष और प्रभावी बनाया गया है। परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि अब तक डिजिटलीकरण और फारेंसिक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की गतिविधियां उतनी रफ्तार से नहीं चल पाई हैं जितनी चलनी चाहिए थी। राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं।

पिघलते ग्लेशियरों में जल संकट की आहट

ग्लोबल वार्मिंग का असर

ज्ञानेन्द्र रावत

ग्लोबल वॉर्मिंग जैसे कारकों से दुनियाभर में ग्लेशियरों का पिघलना भविष्य में गंभीर जल संकट ला सकता है वहीं इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, हिंदूकुश, स्विट्ज़रलैंड या ब्रिटेन- सभी क्षेत्रों में यही स्थिति है। बड़ी चिंता यह कि पर्यावरणीय बदलावों के चलते हिमालयी ग्लेशियर भी चपेट में आ रहे हैं।दुनियाभर के ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर हैं। वे तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इनके पिघलने की यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में दुनिया एक-एक बूंद पानी को तरस जायेगी। दरअसल, जलवायु की प्रचंड आंधी ग्लेशियरों को निगल रही है। यह केवल बर्फ का पिघलना नहीं है; इससे बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है, साथ ही यह बुनियादी ढांचे, कृषि उत्पादन और जलीय-स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

वैज्ञानिकों की मानें तो साल 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये पहाड़ यानी ग्लेशियर 650,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। यह सिलसिला जारी है। वेनेजुएला पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के असर के चलते अपने सभी ग्लेशियर खो दिये। बीसवीं सदी के मध्य में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 400 ग्लेशियर गायब हुए। ग्लेशियरों के पिघलने की स्थिति अंटार्कटिका, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आल्प्स, रॉकीज़, आइसलैंड, हिंदूकुश, स्विट्ज़रलैंड या ब्रिटेन-सभी जगह लगभग एक जैसी है।

वर्ष 2010 से पहले आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो बर्फ की चादर बिछी होती थी, उसमें लाखों वर्ग किमी की कमी हो गयी है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा हिमखंड ए 23 फिर खिसक रहा है जो महासागरों की धाराओं द्वारा बहाकर लाया गया है और अभी दक्षिण जार्जिया के गर्म जल की ओर बढ़ रहा है। यहां यह टूटकर पिघलने की प्रक्रिया में है। बर्फ के प्राकृतिक रूप से बढ़ने की क्रिया के कारण यह हिमखंड टूटकर अलग हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है जिसने समुद्र का जलस्तर बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है।ग्रीनलैंड में जहां बीते 13 साल में 2,347 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ गायब हो गयी है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से दुनियाभर में समुद्र के जलस्तर में बदलाव हुआ। मौसम के पैटर्न में भी बदलाव सामने आया है। स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध रोन ग्लेशियर सहित आल्प्स पर्वत श्रृंखला के कई ग्लेशियरों में बर्फ के नीचे सुरंगें और गड्ढे हो गये हैं। तेजी से बढ़ रहे तापमान के कारण अब ग्लेशियर सिर्फ पिघल नहीं रहे हैं, भीतर से खोखले भी हो रहे हैं। हिंदूकुश क्षेत्र के ग्लेशियर से नवम्बर से मार्च तक बर्फ में 23.6 फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। यह बीते 23 सालों में सबसे कम है। नतीजन पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। बर्फबारी में यह गिरावट लगातार तीसरे साल दर्ज की गयी है।

जलवायु बदलाव और स्थलाकृति के कारण मध्य हिमालय का एक ग्लेशियर तेजी से खिसक रहा है। ग्लेशियरों की चिंताओं के बीच यह नया संकट है। वैज्ञानिक इस ग्लेशियर का उद्गम भारत में और निकास तिब्बत की ओर मानते हैं। इससे तिब्बत से लेकर धौलीगंगा तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है।वह हिमालयी क्षेत्र में 37,465 वर्ग किलोमीटर में फैले कुल 9575 ग्लेशियरों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में जमे ताजे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। एशिया की 10 प्रमुख नदियों को पानी देने वाले इन ग्लेशियरों से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी तीन नदियां विभाजित हुई हैं। कश्मीर में भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यहां भी पानी का संकट है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कानपुर की बड़ी छलांग

देश में 13वें और यूपी में 5वें स्थान पर

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। स्वच्छता के क्षेत्र में कानपुर नगर निगम ने इस बार बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों की श्रेणी में कानपुर ने 13वीं रैंक प्राप्त की है। यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में पांच पायदान बेहतर है, जब कानपुर 18वें स्थान पर था। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश में इस श्रेणी में कानपुर पांचवां सबसे स्वच्छ शहर बन गया है।

यह रैंकिंग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। देश के टॉप तीन शहरों में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहले, आगरा दूसरे, प्रयागराज तीसरे, गाजियाबाद चौथे और कानपुर पांचवें स्थान पर है।

गंगा किनारे बसे 88 नगरों की श्रेणी में गंगा की सफाई के पैमाने पर भी कानपुर ने बड़ी छलांग लगाई है। इस सूची में प्रयागराज पहले, वाराणसी दूसरे और कानपुर तीसरे स्थान पर रहा है। यह सफलता वाटर बॉडीज की साफ-सफाई में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मिली है।

अब ओडीएफ प्लस से वाटर प्लस की ओर

कानपुर नगर निगम को इस बार पहली बार वाटर प्लस कैटेगरी में स्थान मिला है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि शहर खुले में शौच से मुक्त (ह्रष्ठस्न) होने के बाद अब जल स्रोतों की स्वच्छता की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के कुल 12,500 अंकों में से 11,022 अंक प्राप्त हुए हैं। जबकि पिछले वर्ष 9,500 अंकों में 6,409 अंक ही मिले थे।

प्रमुख स्कोरिंग बिंदु

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन- 96प्रति
स्रोत पर कचरा पृथक्करण- 79प्रति
कचरा प्रोसेसिंग-100प्रति
डंप साइट रेमेडिएशन-95प्रति
आवासीय क्षेत्र की स्वच्छता- 100प्रति
बाजार क्षेत्रों की सफाई- 100प्रति
जल स्रोतों की सफाई- 100प्रति
सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति- 87प्रति

स्वच्छता रैंकिंग का इतिहास

वर्ष	राष्ट्रीय रैंकिंग
2018	65वीं
2019	63वीं
2020	25वीं
2021	21वीं
2022	29वीं
2023	18वीं
2024	13वीं

कानपुर शहर ने स्वच्छता की दिशा में निरंतर सुधार किया है। गंगा की सफाई, कचरा निस्तारण और जनता के सहयोग से अब यह शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आ पहुंचा है। नगर निगम की योजनाएं और नागरिकों की भागीदारी इसी तरह जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब कानपुर देश के शीर्ष 10 स्वच्छ शहरों में शामिल होगा।

(सुधीर कुमार नगर आयुक्त)

कमजोरियां भी बनीं बाधा

शहर की 110 वार्डों में से अब तक केवल 90 वार्डों में ही डोर-टू-डोर कचरा उठान व्यवस्था पूरी तरह लागू हो पाई है। यदि यह कार्य पूर्ण होता, तो कानपुर टॉप 10 शहरों में शामिल हो सकता था। डॉ. अमित सिंह ने बताया कि पहले खत्म किए गए 258 खुले कूड़ाघरों में से लगभग 150 फिर से सक्रिय हो गए थे, जिन्हें दोबारा हटाया गया है। वही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नगर निगम के कर्मचारियों और शहर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाली समय में हम और बेहतर करेंगे।

संसाधनों का विस्तार और नई पहल

नगर निगम ने कूड़ा प्रबंधन के लिए नई पहलें की हैं।

भऊसिंह प्लांट को पुनः चालू कर खाद और (रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल) बनाना शुरू किया गया।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6 आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए गए, जिससे कचरा सीधे प्लांट पहुंचता है।पुराने डंपिंग ग्राउंड का रेमेडिएशन कार्य भी जारी है।

5 स्टार रेटिंग भी मिली

कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में गैरेबेज फ्री सिटी (त्रस्नष्ट) के तहत कानपुर को इस बार 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि पहले 3 स्टार थी। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई कर्मचारियों, नगर आयुक्त कार्यालय और नागरिकों को दिया।

परिषदीय विद्यालयों के स्थलीय निरीक्षण को मंडलवार निकलेंगी टीमें

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन, पठन-पाठन, निर्माण, विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी।

समग्र शिक्षा के तहत मंडलवार दो-दो कुल 36 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो एक से 14 अगस्त के बीच स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अनुसार निरीक्षण टीम को मंडल के कम से कम दो जिलों में एक, एक पीएम श्री विद्यालय, 1 केजीबीवी, 1 परिषदीय प्राथमिक, 1 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी, 1 उच्च प्राथमिक, 1 इंटर, 1 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करना होगा। इन अधिकारियों को सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रगति, विद्यालय जर्जर की स्थिति, स्वीकृत निर्माण की प्रगति, फर्नीचर, नए नामांकन, परिवार सर्वे, लर्निंग बाई डूइंग, बाल वाटिका व यूकेजी अलग से चलने की स्थिति, आईसीटी, स्मार्ट क्लास, खेलकूद सामग्री, ईसीसीई एजुकेटर की तैनाती आदि की स्थिति देखनी होगी। महानिदेशक ने निर्देश दिया है कि निरीक्षण के साथ ही यह अधिकारी मंडल व जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। निरीक्षण व बैठक की रिपोर्ट प्रेरणा निरीक्षण ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसके अनुसार जिला व मंडलीय अधिकारी आवश्यक सुधार की कार्यवाही भी करेंगे।

सेंट्रल स्टेशन पर 5 लाख की चरस के साथ युवक गिरफ्तार

रेलवे पुलिस की सतर्कता से बड़ी कामयाबी, आरोपी बिहार से है, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर।थाना जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह कानपुर सेंट्रल और आरपीएफ कानपुर पोस्ट प्रभारी एस एन पाटीदार की संयुक्त टीम ने गुरुवार देर रात एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 5 लाख रुपये मूल्य की अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी तूफान महतो (उम्र 22 वर्ष) बिहार के जिला पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और वह इस नाजायज चरस को ट्रेन के माध्यम से बिहार ले जाने की फिराक में था।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 17 जुलाई की रात 2:05 बजे की गई जब हैरिसगंज पुल के पास रेलवे ट्रैक किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे संदिग्ध युवक की तलाशी के दौरान 03 किलो 900 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। चरस की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5,00,000 आँकी गई है।यह कार्रवाई रेलवे में हो रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। इस अभियान का संचालन अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा के

निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक कानपुर दुष्यंत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है।

गलती की सजा मिल गई पुलिस की गोली से घायल छेड़छाड़ का आरोपी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सनिगवां की एक 17 वर्षीय इंटर की छात्रा से हुई छेड़छाड़ का मामला अब एक एनकाउंटर तक पहुंच चुका है। आरोपी डिलीवरी बॉय आदित्य गुप्ता को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात करीब 10 बजे अलकनंदा इन्क्लेव के पास पुलिस टीम ने उसे चारों ओर से घेरा। खुद को फंसा देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में जा लगी।

गोली लगने के बाद आदित्य बाइक समेत गिर पड़ा और लंगड़ाते हुए कहा 卐मुझे गलत काम की सजा मिल गई卐। पुलिस ने घायल हालत में उसे तत्काल कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया है।

» पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को किया ट्रैक, फायरिंग में लगी गोली

» सनिगवां की छात्रा से की थी बदसलूकी, सीसी टीवी से हुई पहचान

छात्रा को अकेली देख कर की थी अश्लील हरकत

बुधवार दोपहर करीब 3 बजे सनिगवां की रहने वाली छात्रा किताब लेने अपनी सहेली के घर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक ने पहले उसे देखकर अश्लील टिप्पणियां कीं और फिर छेड़छाड़ कर फरार हो गया। आरोपी ने चेहरे को रूमाल से ढक रखा था।

डर और सदमे में पहुंची छात्रा ने

परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिवार ने तत्काल चकेरी थाने में तहरीर दी।

इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी की पहचान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के 50 से अधिक ष्ष्अङ्क फुटेज खंगाले। इनमें एक क्लिप में बाइक का नंबर साफ दिखा, जिससे आदित्य गुप्ता की पहचान हुई। मुखबिरों की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। चार पुलिस टीमों ने गुरुवार को उसे पकड़ने के लिए अलकनंदा इन्क्लेव के पास घेराबंदी की।

परिवार सम्मानित, पर आरोपी ने किया शर्मनाक काम

आरोपी आदित्य गुप्ता बर्रा विश्व बैंक का रहने वाला है। उसके भाई और भाभी दोनों एयरफोर्स में कार्यरत हैं। पिता की मौत के बाद उसने ग्रेजुएशन अधूरा छोड़ दिया और मां के साथ रहने लगा।

खर्च चलाने के लिए वह फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। बुधवार को वह एक डिलीवरी लेकर सनिगवां गया था, उसी दौरान उसने छात्रा से यह घिनौनी हरकत की।

यह घटना सिर्फ एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ भर नहीं है,

बल्कि यह हमारे समाज में पनपते उस खतरे का संकेत है जहां हर गली–मोहल्ले में असुरक्षित महसूस करने की नौबत आ रही है।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक सख्त संदेश जरूर दिया है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या डिलीवरी की आड़ में घूम रहे ऐसे अपराधियों की स्क्रीनिंग पर्याप्त है?

मीडिया की मार, सड़क किनारे की झाड़ियां हटीं, सफर हुआ आसान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा क्षेत्र के बल्हारामऊ और देवीपुर-चांदपुर मार्ग पर झाड़ियों का अतिक्रमण अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। सड़क किनारे खड़ी विलायती झाड़ियां, जो राहगीरों के लिए खतरे का कारण बनी थीं, उन्हें हटवा दिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे एकमात्र वजह रही – स्वराज इंडिया द्वारा प्रकाशित सच्चाई की खबर। 11 जुलाई, शुक्रवार को पेज 9 पर प्रकाशित रिपोर्ट फ्सड़क किनारे झाड़ियां बनीं जानलेवा, हादसों का लगा है सिलसिला शीर्षक से छपी खबर का जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया।

स्वराज इंडिया
Swaraj India
11 Jul 2025 - Page 9
स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com
कानपुर देहात
कानपुर,शुक्रवार 11 जुलाई, 2025
09
» बल्हारामऊ–देवीपुर मार्ग पर हादसे रोकने के लिए ग्रामीणों की गुहार
» पीडब्ल्यूडी को सूचना देने के बाद भी अफसरों ने नहीं की सुनवाई
सड़क किनारे झाड़ियां बनीं जानलेवा
हादसों का लगा है सिलसिला
स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो
कानपुर देहात। मलासा क्षेत्र के बल्हारामऊ–देवीपुर–चांदपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी झाड़ियां अब राहगीरों के लिए खतरा बन चुकी हैं। सामने से आने वाले वाहनों की दृश्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिससे लगातार हादसों की आशंका बनी रहती है।
स्थानीय निवासी अशोक सिंह ने बताया कि सड़क किनारे विलायती झाड़ियों और पेड़ों की भरमार हो गई है, जो सड़क तक फैल चुकी हैं।
दो दिन पहले ही एक बाइक सवार युवक विपरीत दिशा से आ रहे वाहन को न देख पाने के कारण सड़क की पटरी से नीचे गिर गया, गनीमत रही कि उसे गंभीर चोट नहीं आई।
ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने स्थल पर आकर निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क किनारे उगी इन जानलेवा झाड़ियों को तत्काल हटाया जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।

स्थानीय निवासी अशोक सिंह और शेर सिंह ने पहले ही चेताया था कि सड़क के दोनों ओर झाड़ियां सड़क तक फैल गई हैं। दो दिन पूर्व बाइक सवार के साथ हुई दुर्घटना ने खतरे की गंभीरता को और बढ़ा दिया था। दोनों ओर से आ रहे वाहन एक-दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, जिससे टक्कर की आशंका बनी रहती थी।

जागा प्रशासन, हुई त्वरित कार्रवाई

स्वराज इंडिया की खबर सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रथम हेमंत कुमार ने अवर अभियंता राजेश कुमार को त्वरित निर्देश देते

» हादसे रोकने के लिए पीडब्ल्यू ने शुरू कराई सफाई, राहगीरों ने ली राहत की सांस

» स्वराज इंडिया ने दिखाई थी सच्चाई, जिम्मेदार अफसर हरकत में आए

हुए झाड़ियों की सफाई शुरू करवाई। सफाई कार्य पूरा होते ही रास्ता खुला और लोगों को आवागमन में राहत मिली। स्थानीय लोगों ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए स्वराज इंडिया का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि अगर खबर न छपती तो शायद यह अनदेखी और कई जानें ले लेती।

बिना मान्यता के स्कूल बन रहे शिक्षा का दुश्मन, सरकारी स्कूलों में गिर रही बच्चों की संख्या

» कक्षा 5 तक की मान्यता, फिर भी इंटर तक पढ़ा रहे दर्जनों अवैध स्कूल

» शिक्षा विभाग ने दी एफआईआर की चेतावनी, अभिभावकों से की सतर्क रहने की अपील

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात, माती। जिले के गजनेर, मोहाना और सरवनखेड़ा क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों ने शिक्षा व्यवस्था को

गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिन स्कूलों को केवल कक्षा 5 तक की मान्यता मिली है, वे इंटर तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। वहीं, कुछ स्कूल तो बिना किसी मान्यता के गली-मोहल्लों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। न भवन सुरक्षित, न ही शिक्षक योग्य फिर भी अभिभावकों को भ्रमित कर बच्चों का दाखिला लिया जा रहा है।शिकायतों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई,

ज़मीनी सख्ती नदारद परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। शिक्षकों ने बताया कि कुछ अवैध स्कूल संचालक घर-घर जाकर सरकारी स्कूलों की कमियां गिनाते हैं और अभिभावकों को गुमराह करते हैं। सरवनखेड़ा ब्लॉक में दो दर्जन से अधिक स्कूल बिना मान्यता चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी की गई है और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों से सावधान रहें। बीईओ कार्यालय ने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के दाखिले करने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि, बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद कराया जाएगा। जिनके पास जितनी मान्यता है, वे उतनी ही कक्षा तक संचालन करें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

77 ग्राम पंचायतों में दस्तावेजों का टोटा

25 पर रिकवरी की गाज

» शंकर सिंह, स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। सरकारी धन के दुरुपयोग और लापरवाही का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। 2017-18 और 2018-19 में हुए सोशल ऑडिट के लिए जब 77 पंचायतों से दस्तावेज मांगे गए, तो उनमें से 25 ग्राम पंचायतें आज तक कोई अभिलेख नहीं सौंप सकीं। ऐसे में डीपीआरओ विकास पटेल ने रिकवरी नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि दस्तावेज नहीं मिले तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं माने जिम्मेदार : रिकॉर्ड के अनुसार, 2017-18 में 51 पंचायतों और 2018-19 में 26 पंचायतों ने सोशल ऑडिट के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। कई चरणों में नोटिस जारी करने के बावजूद अभिलेख न मिलने पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 2017-18 की 16 पंचायतें जैसे हवासपुर, बहबलपुर, हथूमा, सतौरा, बनीपारा महाराज, पिपरी पतराहार आदि पर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार 2018-19 की पंचायतें जैसे चिलौली, पिलखिनी, सिठमरा, जिगनिश, सिहारी और दौलतपुर को भी नोटिस जारी हो चुके हैं।

डीपीआरओ विकास पटेल ने बताया कि, ÷अगर पंचायत सचिव और पूर्व प्रधान अब भी जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें अनियमितता का दोषी मानकर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

» 2017-18 और 2018-19 के सोशल ऑडिट में फंसी पंचायतें, कई बार नोटिस के बाद भी नहीं दिए अभिलेख

» डीपीआरओ ने भेजे रिकवरी नोटिस, अब एफआईआर की तैयारी में प्रशासन

डीपीआरओ विकास पटेल

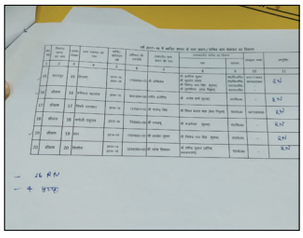

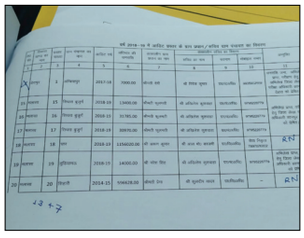

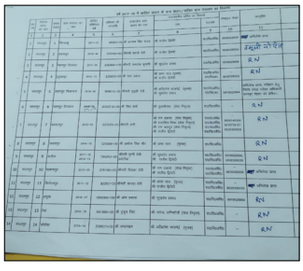

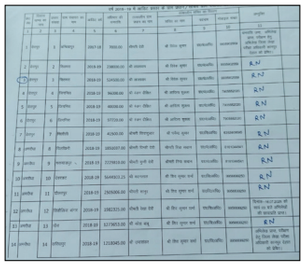

भोगनीपुर में बी-पैक्स समितियां छह साल से बंद, किसान बेहाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के उद्देश्य से बी-पैक्स का नाम तो दे दिया गया, लेकिन हकीकत में किसानों के हालात जस के तस हैं। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मलासा ब्लॉक के डीघ और तुर्कीमऊ गांवों में स्थापित बी-पैक्स समितियां पिछले छह वर्षों से बंद पड़ी हैं। इन समितियों के भवन जर्जर हालत में हैं और तुर्कीमऊ में तो रास्ता इतना सकरा है कि खाद की ढुलाई तक संभव नहीं। समिति भवन में कुछ लोगों ने कब्जा भी कर लिया है। किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए अब दूर-दराज की समितियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय, श्रम और पैसा तीनों की बर्बादी हो रही है।

किसानों की बेबसी, अफसरों के खोखले वादे : समितियों को पुनः शुरू कराने के नाम पर किसानों से सदस्यता शुल्क लिया गया, लेकिन न खाद मिली न कोई सुविधा। ग्रामीणों का कहना है कि दो साल पहले अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि सदस्यता शुल्क से राजस्व जुटाकर समिति फिर से चालू की जाएगी, लेकिन आज तक न कोई अधिकारी आया और न ही कोई नेता। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की विधानसभा होने के बावजूद इन गांवों की उपेक्षा किसानों में आक्रोश पैदा कर रही है। ग्रामीण राजनरायन द्विवेदी, अखिलेश सचान, रामपाल, अश्विनी शुक्ला, श्रीपाल, पप्पू पासी, लवकुश, आदि ने समिति के शीघ्र संचालन की मांग की है ताकि उन्हें उर्वरक और अन्य सुविधाएं समय पर मिल सकें। एडीओ सहकारिता सत्यम शिवहरे ने कहा कि जल्द ही डीघ और तुर्कीमऊ समिति में खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा।

» डीघ व तुर्कीमऊ समितियों पर ताले, जर्जर भवन में अब कब्जे

» सदस्यता शुल्क लेकर भी नहीं मिला लाभ, पुनः संचालन की मांग

बदहाली

गिरदौ स्कूल परिसर में हैंडपंप वर्षों से खराब, चारों तरफ घास और गंदगी का अंबार

स्कूल बना गंदगी का अड्डा, सफाई का जिम्मेदार ही नहीं तय

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री तक सफाई को लेकर संदेश दे चुके हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास खंड मलासा के गांव गिरदौ के संविलियन विद्यालय का हाल देखकर समझ आता है कि सफाई अब भी 'कागज़ी' है। स्कूल परिसर गंदगी और खरपतवार से अटा पड़ा है, और परिसर के गेट के पास ही हैंडपंप वर्षों से खराब पड़ा है।

स्कूल में तैनात इंचार्ज प्रधानाचार्य शिवराम सिंह ने बताया कि 15 दिन पहले सफाईकर्मी से परिसर की सफाई कराने को कहा गया, लेकिन रोस्टर का हवाला देकर मना कर दिया गया। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में सफाई हो चुकी दिखा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि जब न सफाईकर्मी आते हैं, न विभाग की कोई योजना है, तो स्कूलों की सफाई होगी कैसे? पहले यह काम छात्रों से कराया जाता था, लेकिन बालश्रम कानून के चलते यह भी बंद हो गया। आंगनबाड़ी में आने वाले छोटे बच्चों के लिए यह हालत और भी खतरनाक हैं बारिश में सर्प या कीड़े-मकोड़े भीतर घुसने का खतरा बना रहता है।

खंड विकास अधिकारी संजय कुमार कन्नौजिया ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। प्रभारी एडीओ पंचायत अमिता मिश्रा को तुरंत सफाई कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वाराणसी में सीएम योगी का दौरा: विकास परियोजनाओं की समीक्षा, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को काशी पहुंचे और अपने दौरे की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन के साथ की। श्रावण मास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में षोडशोपचार विधि से पूजन कर जनकल्याण की कामना की और मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके पश्चात उन्होंने कालभैरव मंदिर में भी विधिवत पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने इसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने सलारपुर में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की।

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए कि-

विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट चलाने पर सख्त कार्रवाई हो

माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाए। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया में अपनी पहचान छुपा कर अकाउंट चल रहे हैं।

सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रभावित होने वाले धर्मस्थलों को स्थानीय लोगों से संवाद कर, विधि-विधानपूर्वक अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।

सीएम योगी ने दोहराया कि विकास और कानून-व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बाराबंकी: दुर्घटना में घायल भाई-बहन की समय से मदद कर बचाई जान

» मुख्य आरक्षी विनीत कुमार पाण्डेय हुए सम्मानित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बाराबंकी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के चौपला तिराहा के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क किनारे खड़ी एक युवती और उसके भाई को एक अनियंत्रित डीसीएम वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के समय मौके पर ड्यूटी पर तैनात मुख्य आरक्षी (यातायात) विनीत कुमार पाण्डेय ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दोनों घायलों को जिला अस्पताल, बाराबंकी भिजवाया। समय रहते उपचार मिलने से दोनों की जान बच सकी, जिससे लोगों ने मुख्य आरक्षी के सेवा भाव और मानवता की सराहना की।इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने मुख्य आरक्षी विनीत कुमार पाण्डेय को प्रशस्ति पत्र व 1,000 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।बाराबंकी पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि ऐसे कर्मठ और संवेदनशील पुलिसकर्मियों की तत्परता ही पुलिस की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अयोध्या फूड डिपार्टमेंट में चल रही 'पोस्टिंग पॉलिटिक्स'

» घोटाले का स्वाद कड़वा, लेकिन चाट रहे हैं कुछ मीठा चेहरा

» सहायक खाद्य आयुक्त की मनमानी चालू है

» डिपार्टमेंट में चल रहा है ट्रांसफर का गुप्त घोटाला एक्सप्रेस

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अयोध्या एक बार फिर सवालों के घेरे में है इस बार निशाने पर है ट्रांसफर घोटाला। विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने खुद शासन स्तर पर शिकायत भेजकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के दायरे में हैं सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय एवं अभिहित

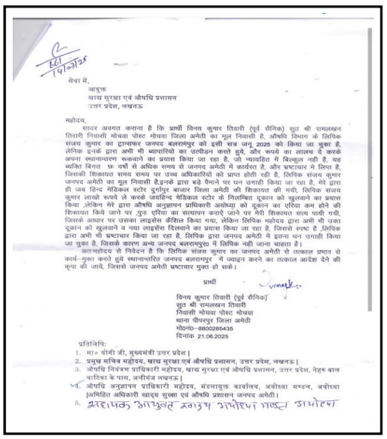

अधिकारी मानिक चंद्र सिंह, जिन पर शासनादेशों को ताक पर रखकर अपने 'चहेतों' की तैनाती कराने का आरोप है।

डॉ. त्रिपाठी के अनुसार, शासनादेश संख्या 31/2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र परिवर्तन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सहमति अनिवार्य है। लेकिन विगत दो वर्षों से इस व्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। सहायक आयुक्त द्वितीय सीधे डीएम को प्रस्ताव भेजते हैं और अधिकारियों की पसंदीदा पोस्टिंग करवा देते हैं बिना विभागीय अनुक्रम के पालन के।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉ. त्रिपाठी ने इस पूरे कृत्य के दस्तावेजी सबूत संलग्न कर शासन को भेजे हैं जिसमें अनुमोदन के प्रस्ताव, शासनादेश और तैनाती आदेश शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह महज लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक साज़िश है जो अपने ही विभाग के नियमों को नष्ट कर रही है।

मामले के बड़े सवाल

क्या ट्रांसफर को 'कमाई और कृपा' का जरिया बना लिया गया है?

जब शीर्ष अधिकारी को ही दरकिनार कर दिया जाए, तो फिर नियमों का क्या मूल्य बचता है?क्या यह घोटाला सिर्फ अयोध्या तक सीमित है, या और जिलों में भी चल रही है यही 'गुप्त पोस्टिंग पॉलिसी'?

स्वराज इंडिया की मांग

यह मामला सिर्फ आंतरिक अनुशासन का नहीं, बल्कि नैतिक प्रशासन और सुशासन की कसौटी पर एक गंभीर परीक्षा है। शासन को चाहिए कि तत्काल जांच कर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। वरना अयोध्या जैसे संवेदनशील जिले में खाद्य सुरक्षा की 'सुरक्षा' खुद खतरे में पड़ जाएगी।

अयोध्या के सैकड़ो जर्जर भवन सावन मेले में बन सकते हैं खतरे की घंटी

» नगर निगम की नोटिसें धरी की धरी

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। सावन झूला मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ने को तैयार है, लेकिन इस आस्था की डगर में जर्जर इमारतें मौत का साया बनकर खड़ी हैं। अयोध्या नगर निगम ने बीते वर्षों में 150 से अधिक खस्ताहाल भवनों को लेकर नोटिस जारी किए, लेकिन भवन स्वामियों की लापरवाही और जिम्मेदारों की सुस्ती के कारण आज भी यह ढांचे ज़मीनी कार्रवाई से कोसों दूर हैं।

स्वर्गद्वार, प्रमोदवन, ऋणमोचन घाट जैसे आस्था के प्रमुख मार्गों पर मौजूद जर्जर भवन किसी भी क्षण ढह सकते हैं। सावन के पावन झूला मेले में इन रास्तों से लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा अधर में है। नगर निगम की ओर से हर साल सूची बनाई जाती है, नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई शून्य के बराबर।छोटी छावनी मार्ग पर जर्जर भवनों की भरमारमणिराम दास छावनी की ओर जाने वाले प्रमोदवन मार्ग पर अनेक पुराने भवनों की हालत बेहद चिंताजनक है। छोटी कुटिया और बड़ी कुटिया जैसे स्थानों पर भवनों की दीवारें झुक चुकी हैं। महंत रामकृष्ण दास ने प्रशासन से अपने मंदिर भवन को गिराने की अनुमति मांगी है ताकि संभावित हादसे को रोका जा सके। कुछ भवन मालिकों ने अदालत से भवन गिराने की इजाजत भी ले रखी है, लेकिन अमल की रफ्तार मंथर है। आरएम द्वारा 20 जून 2025 को जारी आदेश के बावजूद संबंधित निर्माण अभी भी जस का तस खड़ा है।

बदलती अयोध्या, लेकिन इमारतें वही की वही

अयोध्या धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बन रही है, लेकिन जर्जर भवनों की यह परछाईं उसकी सुंदरता और सुरक्षा दोनों को चुनौती दे रही है। प्रशासन की चुप्पी, लापरवाह स्वामी और खतरे में श्रद्धालु सावन के स्वागत में अयोध्या तैयार है, लेकिन मौत छिपी है ईंटों की दरारों में।

जिला पंचायत के चार साल बेमिशाल की भयावह तस्वीर

» नगर निगम की नोटिसें धरी की धरी

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार के चार साल पूरे होते-होते विकास की गंगा बहने के दावे ज़ोरों पर हैं। हर दिन कहीं न कहीं सड़क उद्घाटन, सीसी रोड निर्माण और नई परियोजनाओं के शुभारंभ की खबरें आ रही हैं। लेकिन जब मीडिया की टीम ने जमीनी पड़ताल की, तो तस्वीर एकदम उलटी निकली।

विकासखंड अमानीगंज के अंतर्गत तुलापुर ग्राम पंचायत का हाल देखकर विकास शब्द खुद शर्मसार हो गया। जयराजपुर संपर्क मार्ग से तुलापुर तक की सड़क एक दशक पहले जिला पंचायत निधि से बनी थी, लेकिन उसके बाद न विधायक, न सांसद और न ही जिला पंचायत ने उसकी सुध ली। आज यह सड़क गड्ढों और कीचड़ का जाल बन चुकी है।स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार विधायक और जिला पंचायत से मरम्मत की गुहार लगाई, मगर आश्वासनों की चादर तनी रही, और सड़क की हालत दिन पर दिन बिगड़ती रही। जलभराव से सड़क पर फिसलन बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों का सवाल है–क्या विकास सिर्फ शहरी तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह गया है? जब इस मामले में जिला पंचायत के जेई राजू श्रीवास्तव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि सड़क के मरम्मत कार्य के लिए टेंडर हो चुका है, और एक महीने के भीतर कार्य शुरू होने की संभावना है। लेकिन सवाल अब भी कायम है। चार सालों में एक सड़क भी नहीं बनी तो विकास की गंगा आखिर बही कहां?

तलाक मांगा तो हाथ-पैर पर सुसाइड नोट लिख दी जान

'मुझे कमरे में बंद करके पीटा... कई दिन भूखा भी रखा'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने दो साल बाद ही बागपत जिले के रठौड़ा गांव की मनीषा (24) से तलाक मांग लिया। इस पर महिला ने मंगलवार रात कीटनाशक निगल कर खुदकुशी कर ली। परिजनों को उसका शव बुधवार की सुबह घर में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जान देने से पहले मनीषा ने अपने शरीर पर सुसाइड नोट लिखा और उसमें अपनी मौत के लिए पति समेत अन्य ससुराल वालों को जिम्मेदार बताया।

"रठौड़ा में मनीषा की मौत के मामले में परिजनों की तरफशिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। मनीषा के शरीर पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था और उसने ससुराल वालों के उत्पीड़न के बारे में काफी लिखा है।
-सूरज कुमार राय, एसपी

मुझे पति ने कमरे में बंद करके पीटा और कई दिन भूखा भी रखा : कीटनाशक निगलने से पहले मनीषा ने शादी के बाद अपनी हर पीड़ा को हाथ और पैर पर लिखा। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मौत के जिम्मेदार पति, सास, ससुर और दो देवर हैं, जो रठौड़ा आकर मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देकर गए हैं। उसने लिखा कि पति ने मेरी बहुत पिटाई की और कमरे में बंद करके कई दिनों तक भूखा भी रखा। इसके बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गोलियां खिला गर्भपात कराया गया। गांव में हुई पंचायत में पति ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और मेरे परिवार वालों की बेइज्जती कर तलाक के लिए कहा।

दो बार पंचायत के बाद भी नहीं बनी बात : रठौड़ा निवासी विवेक ने बताया कि वर्ष 2023 में मनीषा की शादी में दहेज में बुलेट बाइक दी गई थी। इसके बाद ससुराल वाले ज्यादा दहेज मांगने लगे। आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर मनीषा को उसका पति पीटता था। शादी के पांच माह बाद ही अपनी बहन को लेकर रठौड़ा आना पड़ा। गांव समाज के लोगों की पंचायत हुई तो दो बार दोनों पक्षों में समझौता हुआ लेकिन ससुराल में मनीषा का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ।

सोलर प्लांट घोटाले व जमीन अधिग्रहण घपले में चार्जशीट दाखिल हुई

आईएएस अभिषेक प्रकाश की बहाली पर संकट बढ़ा

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

लखनऊ। सोलर प्लांट कंपनी से रिश्वतखोरी और भटगांव जमीन अधिग्रहण घोटाले में निलंबित आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नियुक्ति विभाग ने उन्हें दोनों मामलों में चार्जशीट जारी कर दी है। अब अभिषेक प्रकाश को 15 दिन के भीतर चार्जशीट के सभी बिंदुओं पर जवाब देना होगा।

2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर इन्वेस्ट यूपी में सीईओ रहते हुए एक दलाल के जरिए सोलर प्लांट कंपनी से 400 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें 20 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा लखनऊ के जिलाधिकारी रहते हुए उन पर भटगांव भूमि अधिग्रहण घोटाले को नजरअंदाज करने के आरोप हैं।

वर्ष 2011 में डिफेंस कॉरिडोर के लिए सरोजनीनगर के भटगांव क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया गया था, जिसमें मुआवजे की बड़ी धनराशि किसानों को दिए बिना हड़प ली गई। आरोप है कि तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे।

राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की जांच रिपोर्ट में इस गड़बड़ी के लिए तत्कालीन डीएम और पीसीएस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर गंभीर रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग और औद्योगिक विकास विभाग से रिपोर्ट तलब की थी, जिनके आधार पर अब चार्जशीट दी गई है।

वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस प्रकरण को लेकर योगी सरकार पर कई बार निशाना साधा है। अब सभी की निगाहें आईएएस अभिषेक प्रकाश के जवाब पर टिकी हैं। अगर उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया, तो जांच अधिकारी की नियुक्ति कर विस्तृत जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इससे उनके सेवा में पुनः बहाल होने की संभावनाएं और धुंधली हो गई हैं।

» मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें 20 मार्च को निलंबित कर दिया गया

» राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग से रिपोर्ट तलब की थी

पिछली बार पांच पैसे हुए थे कम

अब पेट्रोल-डीजल के दाम होंगे कम!

नई दिल्ली। क्या देश में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो सकते हैं। यह चर्चा तेजी से हो रही है। इसके पीछे वजह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान है। बयान के मुताबिक यदि कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक 65 डॉलर प्रति बैरल पर रहीं तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती हो। उन्होंने ये बात दिल्ली में चल रही 'ऊर्जा वार्ता 2025' में कही। पेट्रोल-डीजल की कीमतें पिछली बार 9 महीने पहले घटी थी। अभी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94.77 रुपये है। वहीं डीजल का दाम 87.67 है। इसके पहले 29 अक्टूबर 2024 को पेट्रोल का दाम 94.72 रुपये था। वहीं डीजल का दाम 87.62 रुपये था। तब पेट्रोल-डीजल में 5 पैसे की कमी की गई थी।

भंडाफोड़ | शिविरों में श्रद्धालुओं के पार कर देते थे मोबाइल, पर्स और कीमती सामान

कावड़ियों के भेष में चोर, 5 गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुजफ्फनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कांवड़ सेवा शिविरों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये लोग कांवड़ियों का भेष धारण कर शिविरों में रुकते थे। वहां आराम कर रहे श्रद्धालुओं के मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान चुरा लेते थे। पुलिस को लगातार इन संदिग्धों की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी।

14 जुलाई 2025 को विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी अपनी उपस्थिति का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए। गिरफ्तार आरोपियों में सुहैल उर्फ चौकस उर्फ शेरखान (22), आसिफ (20), अफसार (24), शाहिद (20) और आबिद शामिल हैं। पुलिस ने पत्रकार वार्ता में इस मामले का खुलासा किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क है और यात्रा मार्ग पर विशेष सुरक्षा अभियान चला रही है।